

[2023] 5 एस. सी. आर 416

रविकुमार धनसुखलाल मेहता और एक अन्य

बनाम

गुजरात उच्च न्यायालय और अन्य।

(2023 की रिट याचिका (सी) संख्या 432)

12 मई, 2023

[एम. आर. शाह और सी. टी. रविकुमार, न्यायाधिपतिगण]

न्यायपालिका: उच्च न्यायपालिका-जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जिला न्यायाधीश नियम 2005 के संवर्ग में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों की पदोन्नति ने जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में 65 प्रतिशत पदों को योग्यता सह वरिष्ठता के सिद्धांत के आधार पर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों के बीच पदोन्नति द्वारा भरने और उपयुक्तता परीक्षण में उत्तीर्ण होने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों की जिला न्यायाधीश के संवर्ग में पदोन्नति के लिए चयन सूची जारी करना (65 प्रतिशत कोटा)-याचिकाकर्ताओं द्वारा पदोन्नति के लिए सिफारिश नहीं की गई है, भले ही वे पदोन्नत किए गए से अधिक अंक रखते हों-याचिकाकर्ताओं द्वारा रिट याचिका को चुनौती देते हुए

18.04.2023 68 उम्मीदवारों की नियुक्ति को अधिसूचित किया गया, जो रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन है: उच्च न्यायालय ने केवल मानदंड प्राप्त करने के उद्देश्य से योग्यता पर विचार किया और उसके बाद वरिष्ठता-सह-योग्यता की ओर रुख किया और इस प्रकार दिया अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के विपरीत और 2005 के नियमों और भर्ती सूचना के विपरीत उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत के अनुसार-उच्च न्यायालय ने एक गलत तरीका अपनाया

विधि-इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा जारी आक्षेपित चयन सूची और जिला न्यायाधीश के संवर्ग को पदोन्नति प्रदान करने वाली राज्य सरकार द्वारा जारी बाद की अधिसूचना अवैध और प्रासंगिक नियमों और विनियमों के विपरीत और यहां तक कि अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के विपरीत, इस प्रकार, राज्य सरकार इस न्यायालय द्वारा सुनवाई की अगली तारीख तक इंतजार नहीं कर सकती थी-वर्तमान में संबंधित पदोन्नति ने पदोन्नति पद पर अपनी पोस्टिंग ग्रहण नहीं की है, उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है, इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा जारी चयन सूची का आगे का कार्यान्वयन और संचालन और राज्य द्वारा जारी बाद की अधिसूचना।

416 रविकुमार धनसुखलाल मेहता और ए. एन. आर. वी. गुजरात और ओ. आर. एस. का नमस्ते न्यायालय।

सरकार को रोक दिया गया है-भारत का संविधान-कला। 14 , 32 - गु.

राज्य न्यायिक सेवा नियम, 2005।

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य। बनाम भारत संघ

पर। बी. वी. शिवैया और अन्य। बनाम
के. अडांकी बाबू और अन्य।

(1998) 6 एससीसी 720: [1998] 3 एस. सी. आर. 782; केरल राज्य

और एन. आर. बनाम एन. एम. थॉमस और अन्य। (1976) 2 एस. सी. सी 310

: [1976] 1 एस. सी. आर. 906; श्रीराम तोमर और अन्र. बनाम।

प्रवीण कुमार जग्गी और अन्य। (2019) 5 एससीसी 736:

[2019] 6 एस. सी. आर. 590; मनोज परिहार और अन्य बनाम राज्य

जम्मू और कश्मीर और अन्य। एस. एल. पी. (सी) सं. 11039

2022 27 जून, 2022 को निर्णय लिया गया; सी. पी. कालरा बनाम एयर इंडिया

(1994) सप. 1 एस. सी. सी. 454; हेमानी मल्होत्रा बनाम हाई

दिल्ली न्यायालय (2008) 7 एस. सी. सी. 11: [2008] 5 एससीआर 1066;
वी. के. श्रीवास्तव और अन्य। बनाम उत्तर सरकार

प्रदेश और अन्र। (2008) 9 एससीसी 77: [2008] 13 एससीआर

24 ; राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव और अन्य। बनाम. समयुत

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अन्य। (2010) 1 एससीसी 335:

[2009] 15 एस. सी. आर. 936-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1998] 3 एससीआर 782

संदर्भित किया गया है

[1976] 1 एससीआर 906

संदर्भित किया गया है

पैरा 4.2

[2019] 6 एससीआर 590

संदर्भित किया गया है

पैरा 4.2

(1994) सप. 1 एससीसी 454

संदर्भित किया गया है

पैरा 4.4

[2008] 5 एससीआर 1066

संदर्भित किया गया है

पैरा 4.9

पैरा 7 (ii)

[2008] 13 एससीआर 24

संदर्भित किया गया है

[2009] 15 एससीआर 936

पैरा 8.8

संदर्भित किया गया है

[2002] 2 एससीआर 712

उस पर भरोसा करें

पैरा 8.2, 8.3, ई

8.5 , 9 , 10

नागरिक मूल न्यायनिर्णय: लेखन याचिका (सी) नहीं

2023 तक।

((2023) 5 एस. सी. आर. के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत।

बसंत आर., सीनियर एड. , पूर्वश जितेंद्र मलकान, सुश्री धरिता पूर्वश मलकान, आलोक कुमार, दीपक मणि त्रिपाठी, नयन गुप्ता, सुश्री दीपा

गोरसिया, अजीत राव, सौदागर सिंह, सुश्री रूमी चंदा, अधिवक्ता। याचिकाकर्ताओं के लिए। दुष्यंत दवे, एस. वी. राजू, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , संदीप कुमार झा, अक्षत मालपानी, निखिल गोयल, नवीन गोयल, आदित्य कोशी राँय, सुश्री दीपानविता प्रियंका, सुश्री मयूरी रघुवंशी, व्योम रघुवंशी, तुषार अरोड़ा, सुश्री वी. पी. सिंह, सुश्री आकांक्षा राठौर, आदित्य चोकसी, अर्पित गुप्ता, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस रिट याचिका के माध्यम से, रिट याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ-साथ गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियम, 2005 (इसके बाद "नियम, 2005" के रूप में संदर्भित) के नियम 5 का उल्लंघन करते हुए वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों को जिला न्यायाधीश के संवर्ग (65 प्रतिशत कोटा) में पदोन्नत करने के लिए अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई चयन सूची को एक उचित रिट, निर्देश या आदेश के लिए अनुरोध किया है।

12.04.2022 .

2. संक्षेप में वर्तमान रिट याचिका की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं -

2.1 कि यह न्यायालय अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य के मामले में। बनाम भारत संघ और अन्य। , (2002) 4 एससीसी 247, था निर्देश दिया कि उच्च न्यायिक सेवाओं, अर्थात् जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में भर्ती "योग्यता-सह-वरिष्ठता" के सिद्धांत और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर होगी। इस न्यायालय ने आगे भी निर्देश दिया

कि संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा उपरोक्त उचित नियम बनाए जाएंगे।

2.2 उपरोक्त निर्देशों के अनुसरण में, गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियम, 2005 तैयार किया है, जिसमें 50 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग) के बीच पदोन्नति का प्रतिशत संशोधन के माध्यम से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया है।

23.06.2011 पर नियम, 2005। नियम, 2005 के नियम 5 (1) (i) के अनुसार जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में 65 प्रतिशत पदों को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों में से पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा।

" योग्यता-सह-वरिष्ठता का सिद्धांत और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करना।

2.3 अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया

योग्यता सह वरिष्ठता के सिद्धांत के आधार पर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों में से जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में पदोन्नति और 65 प्रतिशत रिक्तियों को भरने के लिए एक उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए भर्ती सूचना-जिला न्यायाधीश (65 प्रतिशत) दिनांक 1 के माध्यम से विज्ञापन। उक्त अधिसूचना विचाराधीन क्षेत्र में आने वाले वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों के संवर्ग में 205 न्यायिक अधिकारियों की सूची के साथ जारी की गई थी।

2.4 इस स्तर पर, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भर्ती में

स्वयं ध्यान दें, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि "वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों में से जिला न्यायाधीश (65 प्रतिशत) के संवर्ग में पदोन्नति योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर होगी। भर्ती सूचना में भी उपयुक्तता परीक्षा का एक संदर्भ था, जिसमें पदोन्नति के लिए एक न्यायिक अधिकारी की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए चार घटक शामिल थे, जो निम्नानुसार हैं:

उपयुक्तता परीक्षण के घटक

निशानियाँ

श्री.

नहीं।

लिखित परीक्षा (उद्देश्य प्रकार-एमसीक्यू)

1 .

100

2 .

वार्षिक परीक्षा और मूल्यांकन

20

पिछले पाँच वर्षों की गोपनीय रिपोर्ट।

3 .

पिछले वर्ष के औसत निपटान का आकलन

न्यायिक अधिकारी के पाँच वर्ष
चिंतित हैं।

द्वारा दिए गए निर्णयों का मूल्यांकन

4 .

संबंधित न्यायिक अधिकारी के दौरान

पिछले एक वर्ष की अवधि।

2.5 उच्च न्यायालय द्वारा 16.10.2022 पर लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी।

उच्च न्यायालय ने 175 न्यायिक अधिकारियों की सूची घोषित की, जो लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए और लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। याचिकाकर्ताओं को लिखित परीक्षा में भी योग्य घोषित किया गया था।

2.6 उच्च न्यायालय ने 18.11.2022 पर महीने के हिसाब से कहा

उन उम्मीदवारों के दीवानी और आपराधिक मामलों के निपटारे के निर्णयों की सूची, जिन्हें दिनांकित 17.11.2022 सूची के माध्यम से योग्य घोषित किया गया है। उच्च न्यायालय ने 10.03.2023 पर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों की चयन सूची घोषित की। चयनित उम्मीदवारों के अंक 148.50 से 100.50 अंकों के बीच थे। याचिकाकर्ता नंबर 1 ने 200 अंकों [2023] 5 एस. सी. आर. में से 135.50 हासिल किया।

और याचिकाकर्ता संख्या 2 ने 200 में से 148.50 अंक प्राप्त किए और जैसे कि उच्च अंक होने के कारण, उन्हें नियुक्त नहीं किया गया और/या उनके नामों की जिला न्यायाधीश के संवर्ग में पदोन्नति के लिए सिफारिश नहीं की गई, याचिकाकर्ताओं ने 27.03.2023 पर वर्तमान रिट याचिका दायर की।

2.7 इस न्यायालय ने वर्तमान रिट याचिका में नोटिस जारी किया

13.04.2023 और एक विस्तृत बोलने का आदेश पारित किया, जो निम्नानुसार है:

" याचिकाकर्ता (ओं) की ओर से यह मामला है कि

भर्ती नियम, जिला न्यायाधीश के पद को योग्यता सह-वरिष्ठता के सिद्धांत के आधार पर 65 प्रतिशत आरक्षण रखते हुए और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करके भरा जाना है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

उपरोक्त के बावजूद अधिसूचना के माध्यम से नियुक्तियाँ करते समय दिनांक 10.03.2023, योग्यता-सह-वरिष्ठता सिद्धांत को मंजूरी दी गई है और नियुक्तियाँ वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर की जाती हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहाँ तक याचिकाकर्ता नं। 1 उन्होंने 200 में से 135.5 अंक प्राप्त किए हैं और याचिकाकर्ता नं। 2 है।

200 में से उच्चतम अंक, यानी 148.5 भी प्राप्त किए हैं और उपरोक्त के बावजूद, जिन उम्मीदवारों के कम अंक हैं, उन्हें दिया गया है

नियुक्त किया गया।

दस्ती सेवा की भी अनुमति है।
याचिकाकर्ताओं के लिए याचिका की प्रति देने के लिए खुला रहेगा।

प्रत्यर्थी संख्या के लिए स्थायी वकील पर। 1 और 2 "।

2.8 वर्तमान रिट की प्रति के साथ दिए जाने के बावजूद

याचिका और हालांकि नोटिस 28.04.2023 पर वापस करने योग्य बनाया गया था और वर्तमान रिट याचिका लंबित होने पर, राज्य सरकार ने जल्दबाजी में जारी किया 68 उम्मीदवारों की नियुक्ति को अधिसूचित करने वाली अधिसूचना 18.04.2023,

जिनका चयन दिनांक 10.03.2023 की चयन सूची द्वारा किया गया था, हालांकि, अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि नियुक्तियाँ/पदोन्नति वर्तमान रिट याचिका के परिणाम के अधीन होगी।

3. श्री आर. बसंत, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री पूर्वश जितेंद्र मलकन के साथ पेश हुए, जो विद्वान वकील हैं।

रिट याचिकाकर्ताओं। श्री एस. वी. राजू, विद्वान ए. एस. जी. राज्य की ओर से पेश हुए हैं और सुश्री दीपानविता प्रियंका, विद्वान वकील भी राज्य की ओर से पेश हुई हैं। श्री दुष्यंत दवे, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता/वकील संबंधित पदोन्नतियों की ओर से पेश हुए हैं।

न्यायाधीश को योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों में से पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त के बावजूद, उच्च न्यायालय के साथ-साथ राज्य सरकार ने पदोन्नति दी है वरिष्ठता-सह-योग्यता के सिद्धांत और योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत को लागू करने की अनुमति दी गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 ने 200 अंकों में से 135.5 अंक प्राप्त किए हैं और याचिकाकर्ता संख्या 2 ने 200 अंकों में से भी उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं, यानी 148.5 और उपरोक्त के बावजूद, कम अंक रखने वाले उम्मीदवारों को पदोन्नत किया गया है।

4.2 "योग्यता-सह-वरिष्ठता" और "वरिष्ठता-सह-योग्यता" के सिद्धांत पर, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता निम्नलिखित निर्णयों पर बहुत अधिक भरोसा किया है:

(i)

बी. वी. शिवैया और अन्य। बनाम के. अडांकी बाबू और अन्य। ,

(1998) 6 एससीसी 720;

(ख)

केरल और अन्र राज्य। बनाम एन. एम. थॉमस और अन्य। ,

(1976) 2 एस. सी. सी 310;

(iii) श्रीराम तोमर और अन्र। बनाम प्रवीण कुमार जग्गी

और ओआरएस। , (2019) 5 एस. सी. सी. 736 और

(iv) मनोज परिहार और अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय का निर्णय। , 2022 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 11039 27 जून, 2022 को तय की गई।

4.3 यह आगे संबंधित याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बसंत द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि विधि अपनाई गई

उच्च न्यायालय द्वारा जिला न्यायाधीश के पद पर पदोन्नति के लिए चयन सूची तैयार करना बिल्कुल अवैध है और नियम, 2005 [2023] 5 एस. सी. आर. के बिल्कुल विपरीत है।

वर्ष 2011 में और संशोधन किया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय के अनुसार और इसलिए जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि 68 उम्मीदवारों के चयन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को दिनांकित 10.03.2023 चयन सूची के माध्यम से समझाते हुए, यह नीचे दिया गया है:

50 प्रतिशत अंकों के साथ घटक। इसे प्राप्त करने पर, अंतिम चयन वरिष्ठता पर आधारित होगा। तदनुसार, एक चयन उम्मीदवारों की सूची तैयार की गई थी। 68

योग्यता फीडर ग्रेड (निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और सेवा की अवधि रखने वाले) में सभी योग्य उम्मीदवारों को एक प्रक्रिया के अधीन करना है। एक निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक योग्यता का मूल्यांकन करना और फिर उन उम्मीदवारों को पदोन्नत करना जिनके पास वरिष्ठता के क्रम में न्यूनतम आवश्यक योग्यता पाई जाती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि उच्च न्यायालय उपरोक्त पद्धति के नामकरण का उपयोग योग्यता-सह-वरिष्ठता के रूप में करता है, लेकिन वास्तव में उसने वरिष्ठता-सह-योग्यता के सिद्धांत का पालन किया है। अपने उपरोक्त निवेदन के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने एन. एम. थॉमस और अन्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा किया है। (ऊपर) के साथ-साथ सी. पी. कालरा बनाम एयर इंडिया (1994) सप के मामले में। 1 एससीसी 454। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सी. पी. कालरा (उपर्युक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने फैसला सुनाया

है कि हालांकि उक्त मामले में नियमों में योग्यता सह-वरिष्ठता का उल्लेख है, लेकिन नियम वरिष्ठता सह-योग्यता की विधि को विस्तृत रूप से निर्धारित करते हैं।

4.5 याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि कानून की तय स्थिति के अनुसार, जब

उसी का पूर्ण प्रस्थान। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने वरिष्ठता को सबसे कम पहचाना है पदोन्नति के लिए मानदंड, जिसे बनाए नहीं रखा जा सकता है, यदि नियम, 2005 के तहत प्रदान किए गए "योग्यता सह-वरिष्ठता" के सिद्धांत का पालन किया जाना है।

4.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी मामले में, वर्तमान मामले में,

जिला न्यायाधीश के संवर्ग में नियुक्ति वर्ष 2011 में संशोधित नियमों, 2005 द्वारा शासित होती है, जिसमें विशेष रूप से निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं - योग्यता सह-वरिष्ठता के सिद्धांत और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर जिला न्यायाधीश के पद पर पदोन्नति।

4.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2019 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति करते समय

गुजरात का उच्च न्यायालय इसका अनुसरण करेगा। रिलायंस को 2019 की रिट याचिका (एस) संख्या 3771 दिनांक 29.06.2022 के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले पर रखा गया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि कलकत्ता के उच्च न्यायालय ने भी योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत का उसी तरीके से पालन किया है, जिसके लिए याचिकाकर्ता प्रार्थना कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जारी जिला न्यायाधीश कैडर के लिए सामान्य पदोन्नति-2020 का योग्यता-वार परिणाम यह दर्शाता है कि पहले 17 अधिकारी, जो योग्यता में हैं, का चयन किया जाता है और जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए उनकी सिफारिश की जाती है। 4.8 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा जवाबी हलफनामे में प्रस्तुत योग्यता सूची से, यह संतुष्ट होगा कि याचिकाकर्ताओं को

पहले 68 उम्मीदवारों में शामिल किए गए हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि उच्च न्यायालय ने "योग्यता-सह-वरिष्ठता" के सिद्धांत का पालन किया होता, तो उस मामले में याचिकाकर्ताओं को जिला न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया जाता क्योंकि वे अधिक मेधावी होते और पदोन्नत उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक रखते।

4.9 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार भर्ती सूचना में पात्रता के मानदंडों का उल्लेख किए जाने के बाद भी, "योग्यता-सह-वरिष्ठता" और "उपयुक्तता परीक्षा", इसके बाद, उच्च न्यायालय और राज्य के लिए अतिरिक्त आवश्यकता/योग्यता को शामिल करने के लिए खुला नहीं था। प्रक्रिया के दौरान या चयन प्रक्रिया के बाद वरिष्ठता की योग्यता। रिलायंस को इस मामले में इस अदालत के फैसले पर रखा गया है

4.10 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान रिट याचिका को अनुमति देने का अनुरोध किया जाता है। 5. राज्य की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया जाता है। उच्च न्यायालय की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:

(i)

कि अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान रिट याचिका भारत के संविधान पर विचार नहीं किया जा सकता है और याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय के पहले दृष्टिकोण पर भेजा जा सकता है।

अदालत। ;

((ख)

कि वर्तमान मामले में, चयन सूची प्रकाशित की गई थी 10.03.2023 और राज्य सरकार को स्थानांतरित कर दिया गया था

आवश्यक नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए एक ही दिन। ; कि वर्तमान मामले में, एक चयन समिति थी

(iii)

2022 के चयन के उद्देश्य से गठित। 205 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों का एक फीडर कैडर बनाया गया था। जिनके पास कम से कम दो साल की योग्यता सेवा है। सूची 12.04.2022 और याचिकाकर्ताओं पर अपलोड की गई थी

उक्त सूची में सूचीबद्ध थे। ; कि एक उम्मीदवार की उपयुक्तता के चार घटक थे,

((iv)

जो भर्ती सूचना में विधिवत परिलक्षित हुए थे। "योग्यता" योग्यता के लिए एक उम्मीदवार को 50 प्रतिशत अंकों के साथ प्रत्येक घटक में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

कुल मिलाकर। इसे प्राप्त करने पर, अंतिम चयन होगा

वरिष्ठता पर आधारित हो। तदनुसार, 68 उम्मीदवारों की एक चयन सूची तैयार की गई थी, जो सी. पी. कालरा (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले के अनुरूप थी। ;

(v)

कि चयन सूची पूर्ण न्यायालय के समक्ष रखी गई थी

बैठक और अनुमोदन पर, वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था

10.03.2023 पर उच्च न्यायालय का।;

(vi)

कि कार्यप्रणाली, जिसका उच्च द्वारा पालन किया गया है

वर्ष 2011 से न्यायालय का पालन किया जा रहा है।;

(vii) कि रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा बताई गई कार्यप्रणाली केवल योग्यता के आधार पर चयन की ओर इशारा करती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार जब फीडर कैडर में ऐसे उम्मीदवार शामिल हो जाते हैं जिनके पास केवल दो साल का अनुभव होता है और केवल अंकों का मानदंड देखा जाना है, तो यह केवल योग्यता के आधार पर एक चयन बन जाता है जो इस सिद्धांत को पूरी तरह से स्वीकार करता है -

वरिष्ठता।;

(viii) कि वर्तमान मामले में, चयन के लिए योग्यता को उतनी ही प्राथमिकता दी जाती है जितनी वरिष्ठ उम्मीदवारों के लिए

मेधावी उम्मीदवार, यदि पहली बार में, वे रविकुमार धनंजय मेहता और ए. एन. आर. में विफल रहते हैं।

वी. गुजरात और ओ. आर. एस. का उच्च न्यायालय। [एम. आर. शाह, जे.]

उपयुक्तता परीक्षण में अर्हता प्राप्त करें और उसके बाद शेष

उम्मीदवार प्रत्येक घटक में न्यूनतम अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं और कुल 200 अंकों में से कुल 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इसलिए, एक बार योग्यता निर्धारित हो जाने के बाद, वरिष्ठता हावी हो जाती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इसलिए, "योग्यता-सह-वरिष्ठता" का सिद्धांत दिया गया है

पीछा किया। ;

(ix) कि याचिकाकर्ता इस प्रक्रिया से अवगत थे और

बिना किसी आपत्ति के इसमें भाग लिया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, रिट याचिकाकर्ताओं को ऐसा करने से रोक दिया जाता है

वर्तमान चुनौती। ;

कि वही सूत्र लागू किया गया था जब वर्तमान

(x)

याचिकाकर्ताओं को उनके संबंधित पदों से वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के कैडर में पदोन्नत किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, रिट याचिकाकर्ता, इसके बाद, अपनाई गई उसी पद्धति के संबंध में कोई शिकायत नहीं कर सकते हैं।

जिला न्यायाधीश के पद पर विचार करना। ;

(xi) कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और उड़ीसा उच्च न्यायालय ने भी सिद्धांत की एक ही पद्धति का पालन किया है।

योग्यता-सह-वरिष्ठता। ;

6. अब, जहां तक प्रतिवादियों की ओर से संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान रिट याचिका पर विचार नहीं करने का निवेदन है

भारत का संबंध है, उक्त आपत्ति को खारिज कर दिया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय को उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है और अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य के मामले में इस न्यायालय के पहले के निर्णय को ध्यान में रखते हुए। (ऊपर) और उसके बाद भी संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक और याचिका पर विचार किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान रिट याचिका पर विचार किया जाता है।

7. पदोन्नतियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता,

वर्तमान रिट याचिका का विरोध करते हुए निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:

(i)

कि नियम, 2005 के अनुपालन में बनाए गए हैं

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश। (ऊपर)। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुच्छेद 27 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि [2023] 5 एस. सी. आर. होना चाहिए।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए दो तरीके हों, अर्थात् (i) योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत के आधार पर पदोन्नति और (ii) योग्यता के आधार पर सख्ती से पदोन्नति। द.

पदोन्नति के दो तरीकों के बीच अंतर यह है कि दूसरी विधि में, केवल परीक्षा में न्यायिक अधिकारियों द्वारा प्राप्त योग्यता चयन सूची में उनकी स्थिति निर्धारित करेगी, जबकि पहली विधि के अनुसार पदोन्नति के दौरान विधि, फीडर कैडरों में वरिष्ठता बनाए रखनी होगी। ;

वह वी. के. श्रीवास्तव और अन्य के मामले में। बनाम।

उत्तर प्रदेश सरकार और अन्र. , (2008) 9 एस. सी. सी. 77, इस न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि भले ही योग्यता-सह-वरिष्ठता का सिद्धांत लागू किया जाना है, सिद्धांत यह है कि यदि उम्मीदवार जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में पदोन्नति के लिए पात्र हैं, तो 50 प्रतिशत पदोन्नति के संबंध में फीडर श्रेणी में वरिष्ठता बनाए रखी जानी चाहिए और 25 प्रतिशत पदोन्नति के मामले में, परीक्षा कठोर और सख्ती से योग्यता पर होनी चाहिए और ऐसा उम्मीदवार फीडर श्रेणी में अपने कुछ सहयोगियों, यानी सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग) को हटा सकता है। ; सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से 10 प्रतिशत कोटे के तहत पदोन्नति का माध्यम प्रदान करने का उद्देश्य अपेक्षाकृत कनिष्ठ अधिकारियों में से अधिकारियों को सुधार करने और एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है ताकि वे उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें और तेजी से पदोन्नति प्राप्त कर सकें।

हालाँकि, 65 प्रतिशत कोटे के तहत रिक्तियों को भरते समय पदोन्नति की इस विधि को लागू नहीं किया जाना है। ; योग्यता-सह-वरिष्ठता का मतलब यह नहीं है कि सेवा की अवधि की कोई प्रासंगिकता नहीं है और एक लिखित परीक्षा जो केवल शैक्षणिक ज्ञान का परीक्षण करती है, जो कभी-कभी, कानून का अभ्यास करने के समग्र गुणों, व्यावहारिक अनुभव के बिना प्राप्त की जाती है। ;

पदोन्नति प्राप्त व्यक्तियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने आगे कहा है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से लिए गए निर्णय जिला न्यायाधीशों की भर्ती के लिए लागू नहीं होंगे। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी नियम गुजरात के संबंध में लागू नियमों से अलग और अलग हैं।

विकुमार धनसुखलाल मेहता और ए. एन. आर. वी. गुजरात और ओ. आर. एस. का उच्च न्यायालय। [एम. आर. शाह, जे.]

यह प्रस्तुत किया जाता है कि झारखंड नियमों में नियम 5 के परंतुक में, यह कहा गया है कि वरिष्ठता केवल तभी प्रबल होगी जब योग्यता सभी मामलों में समाप्त हो जाएगी। हालांकि, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है

लागू नियमों में कहा गया है। ;

(vi) उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान को खारिज करने की प्रार्थना की जाती है।

रिट याचिका।

8. शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रासंगिक के अनुसार प्रस्थान नियम, अर्थात् गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियम, 2011 में जिला न्यायाधीश के पद पर पदोन्नति के लिए और संशोधन किया गया ई योग्यता-सह-वरिष्ठता और उत्तीर्णता के सिद्धांत के आधार पर दिया जाता है। क्षमता परीक्षण। संबंधित नियम इस प्रकार हैं: -

(1) जिला संवर्ग में भर्ती

न्यायाधीश निम्नानुसार होगा:

((i)

65 पदों का प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा

के सिद्धांत के आधार पर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के बीच योग्यता-सह-वरिष्ठता और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करना।

((ख)

10 पदों का प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा

प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से योग्यता का आधार

कम से कम पाँच वर्ष की योग्यता सेवा रखने वाले वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों के बीच:

बशर्ते कि जब उम्मीदवार 10 प्रतिशत के लिए उपलब्ध न हों

सीटें या प्रतिस्पर्धी में अर्हता प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं

परीक्षा, फिर खाली पदों को नियमित रूप से भरा जाएगा

उपरोक्त खंड (i) के अनुसार पदोन्नति,
25 पदों का प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

(iii)

न्यायालय: बशर्ते कि सभी
रिक्तियों को विशेष वर्ष में हटा दिया जाएगा और अधूरे पद को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

XXXXXXXXXX "

8.1 यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि भर्ती के अनुसार भी
ई-जिला न्यायाधीश (65 प्रतिशत), जिला संवर्ग में पदोन्नति
ई (65 प्रतिशत) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों में से इस आधार पर होंगे
योग्यता-सह-वरिष्ठता का सिद्धांत और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करना।

3] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यहाँ ऊपर। इस प्रकार, वैधानिक नियमों के अनुसार और यहां तक कि के अनुसार भर्ती सूचना, जिला न्यायाधीश के संवर्ग में पदोन्नति (65 प्रतिशत) योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत के आधार पर होगी और

उपयुक्तता परीक्षण। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि नियम, 2005 को वर्ष 2011 में और संशोधित किया गया है, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है। (ऊपर)। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय से पहले। (ऊपर), उच्च न्यायिक सेवा, अर्थात् जिला न्यायाधीशों और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में पदोन्नति वरिष्ठता-सह-योग्यता के सिद्धांत के आधार पर दी गई थी। उच्च न्यायिक सेवा, अर्थात् जिला न्यायाधीशों और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में पदोन्नति के लिए योग्यता-आधारित मानदंडों की आवश्यकता पर जोर देते हुए, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 27 में कहा:

" 27. एक अन्य प्रश्न जो विचार के लिए आता है, वह है उच्च न्यायिक सेवा यानी जिला न्यायाधीशों और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में पदों पर भर्ती की विधि। वर्तमान में

इस समय, उच्च पदों पर भर्ती के लिए दो स्रोत हैं

न्यायिक सेवा, अर्थात्, अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों के बीच से पदोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा। अधीनस्थ न्यायपालिका न्यायिक प्रणाली की नींव है। इसलिए, किसी भी अन्य आधार की तरह, यह अनिवार्य है कि इसे जितना संभव हो उतना मजबूत होना चाहिए। न्यायिक प्रणाली पर भार अनिवार्य रूप से अधीनस्थ न्यायपालिका पर निर्भर करता है। जबकि हम

शेड्टी आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिसके परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायपालिका के वेतनमान में वृद्धि होगी, साथ ही यह भी आवश्यक है कि न्यायिक अधिकारी, जो मेहनती हैं, अधिक कुशल बनें। यह अनिवार्य है।

कि वे कानून और नवीनतम के ज्ञान से अवगत रहें

घोषणाएँ, और यही कारण है कि शेड्टी

आयोग ने न्यायिक आयोग की स्थापना की सिफारिश की है।

अकादमी, जो बहुत आवश्यक है। साथ ही, हमारी राय है कि एक निश्चित न्यूनतम मानक होना चाहिए,

निष्पक्ष रूप से उन अधिकारियों के लिए निर्णय लिया जाता है जिन्हें अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों के रूप में उच्च न्यायिक सेवा में प्रवेश करना होता है। जबकि हम शेट्टी आयोग से सहमत हैं कि भर्ती रविकुमार धनसुखलाल महिता और ए. एन. आर.

वी. गुजरात और ओ. आर. एस. का उच्च न्यायालय। [एम. आर. शाह, जे.]

उच्च न्यायिक सेवा अर्थात जिला न्यायाधीश संवर्ग में अधिवक्ताओं में से 25 प्रतिशत होना चाहिए और भर्ती की प्रक्रिया लिखित और मौखिक दोनों प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होनी चाहिए, हमारी राय है कि उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नति के लिए अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की उपयुक्तता का परीक्षण करने का एक वस्तुनिष्ठ तरीका होना चाहिए। इसके अलावा, अपेक्षाकृत कम उम्र के लोगों के बीच एक प्रोत्साहन भी होना चाहिए और

अन्य अधिकारियों को सुधार करने और एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए ताकि वे उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें और जल्दी पदोन्नति प्राप्त कर सकें। इस तरह, हम उम्मीद करते हैं कि उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों की क्षमता में और सुधार होगा। इसे प्राप्त करने के लिए, जबकि पदोन्नति द्वारा 75 प्रतिशत और प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा 25 प्रतिशत नियुक्ति का अनुपात

तथापि, उच्च न्यायिक सेवा को बनाए रखने के लिए हमारी राय है कि जहां तक पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का संबंध है, दो तरीके होने चाहिए: 50 उच्च न्यायिक सेवा में कुल पदों का प्रतिशत योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, उच्च

अदालतों को उन उम्मीदवारों के कानूनी ज्ञान का पता लगाने और जांच करने और मामले-कानून के पर्याप्त ज्ञान के साथ उनकी निरंतर दक्षता का आकलन करने के लिए एक परीक्षा तैयार करनी चाहिए और विकसित करनी चाहिए। सेवा में शेष 25 प्रतिशत पद होंगे -

सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर सख्ती से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है जिसके लिए अर्हता प्राप्त होती है

सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) के रूप में सेवा पाँच वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उच्च न्यायालयों को इसमें एक नियम बनाना होगा। ध्यान दें "।

8.2 इसके बाद, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि उच्च न्यायिक सेवा, यानी जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में भर्ती 50 प्रतिशत होगी -

सिद्धांत के आधार पर सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग) के बीच पदोन्नति का तरीका (जिसे बाद में बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया है)

योग्यता-सह-वरिष्ठता और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करना। इस प्रकार, इस न्यायालय ने योग्यता-सह-वरिष्ठता और उच्च न्यायिक सेवा के संवर्ग में पदोन्नति के लिए एक उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर स्पष्ट रूप से जोर दिया है। कि यह

न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों/राज्यों को तदनुसार नियमों/विनियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया। इसलिए, उच्च न्यायालय ने गुजरात को तैयार किया

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप राज्य न्यायिक सेवा नियम, 2005।

(ऊपर)।

23] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8.3 वर्तमान मामले में और उच्च न्यायालय की ओर से मामले के अनुसार, काउंटर में इस प्रकार कहा गया है, उच्च न्यायालय ने केवल बेंचमार्क प्राप्त करने के उद्देश्य से योग्यता पर विचार किया है और उसके बाद

50 प्रतिशत। इस प्रकार, लिखित परीक्षा आयोजित करने के बाद, जो उपयुक्तता का आकलन करने के लिए घटकों में से एक है, उच्च न्यायालय ने विचार किया है केवल मानदंड प्राप्त करने के उद्देश्य से योग्यताएँ और उसके बाद वरिष्ठता-सह-योग्यता के सिद्धांत पर स्विच किया गया है और इस तरह

योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए। उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया तरीका अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ के मामले में पैराग्राफ 27 में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के बिल्कुल विपरीत है और

ओआरएस। (ऊपर) और गुजरात राज्य न्यायिक सेवा के विपरीत भी

नियम, 2005 और भर्ती सूचना।

8.4 हमें भर्ती नियम, 2005 और/या यहाँ तक कि भर्ती सूचना में केवल इस उद्देश्य के लिए योग्यता पर विचार करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है।

50 प्रतिशत के मानक को प्राप्त करना। सही तरीका यह होगा कि भर्ती सूचना के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित चार घटकों के आधार पर उन वरिष्ठ लोगों में से योग्यता सूची तैयार की जाए। सिविल न्यायाधीश (तदर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों सहित) जो उस संवर्ग में कम से कम दो वर्ष की अर्हता सेवा रखते हैं और उसके बाद विभिन्न घटकों के तहत प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता सूची तैयार करते हैं और इस तरह केवल योग्यता के आधार पर पदोन्नति देते हैं, तभी इसे योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन करना कहा जा सकता है। इसलिए, वर्तमान मामले में, जिला न्यायाधीश के संवर्ग में पदोन्नति देते हुए, उच्च न्यायालय ने अनुमति दे दी है

8.5 अब, जहां तक प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों-पदोन्नति और उच्च न्यायालय की ओर से यह निवेदन है कि इस प्रक्रिया का पालन 2011 से किया जा रहा है और यहां तक कि अन्य उच्च न्यायालयों में भी इसका पालन किया जा रहा है और इसलिए, यह न्यायालय इस तरह के तरीके में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, उपरोक्त को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सिर्फ इसलिए कि एक गलत यदि यह विधि अवैध और/या इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत पाई जाती है, विशेष रूप से अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य के मामले में, तो इसे बनाए रखने का आधार नहीं हो सकता है। (ऊपर)।

रविकुमार धनसुखलाल मेहता और ए. एन. आर. वी. गुजरात और ओ. आर. एस. का उच्च न्यायालय। [एम. आर. शाह, जे.]

8.6 यहां तक कि पदोन्नति की ओर से आपत्ति यह है कि चूंकि यह न्यायालय जिले के पद पर भर्ती की प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है

न्यायाधीशों और इसलिए, वर्तमान रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है और/या इस पीठ द्वारा, कोई सार नहीं है। जिला न्यायाधीश के पद पर पदोन्नति के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली की नहीं, बल्कि प्रक्रिया की निगरानी की जा रही है। यह न्यायालय इस बात की निगरानी कर रहा है कि क्या मलिक मजहर सुल्तान (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सारिणी को लागू किया जा रहा है। उनका पालन किया जाता है या नहीं और पद समय पर भरे जाते हैं या नहीं। पदोन्नति का तरीका और तरीका विषय नहीं है।

8.7 अब, जहाँ तक सी. पी. कालरा (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर दी गई निर्भरता, की ओर से निर्भर थी

पदोन्नति पाने वाले संबंधित हैं, शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उक्त निर्णय अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय से पहले है। (ऊपर)। वर्तमान मामले में, भर्ती नियमों में विशेष रूप से यह प्रावधान है कि पदोन्नति योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत को लागू करके दी जाएगी, जिसका पालन किया जाना है को।

8.8 अब, जहाँ तक वी. के. श्रीवास्तव और अन्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता की बात है। (ऊपर) पर भरोसा किया

पदोन्नति पाने वालों की ओर से, शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इस न्यायालय के उक्त निर्णय में यह नहीं देखा जा रहा है कि

योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत को मंजूरी दी जानी चाहिए। इस न्यायालय के समक्ष, याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि नियमों के संशोधन से पहले, जिला न्यायाधीश के संवर्ग में पदोन्नति "वरिष्ठता-सह-योग्यता" के सिद्धांत पर आधारित थी और अब, संशोधित नियमों के अनुसार, इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सिद्धांत को "योग्यता-सह-वरिष्ठता" में बदल दिया गया है और इसने सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग) के अधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। हालाँकि, संशोधित नियम पूर्वव्यापी रूप से लागू होते हैं और उस पर, इस न्यायालय ने राज्य की ओर से इस तर्क को नोट किया कि पदोन्नति की प्रक्रिया में, योग्यता अकेले को महत्व नहीं दिया जा रहा था। इस न्यायालय के समक्ष "योग्यता-सह-वरिष्ठता" और/या जिसे "योग्यता-सह-वरिष्ठता" कहा जा सकता है, के सिद्धांत पर कोई सीधा विवाद नहीं था। योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत पर कानून अब तक इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के एक समूह में तय किया गया है। जैसा कि देखा गया है, "योग्यता-सह-वरिष्ठता" के सिद्धांत को लागू करते समय, योग्यता और क्षमता पर अधिक जोर दिया जाता है और वरिष्ठता कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसा कि देखा गया है, "योग्यता-सह-वरिष्ठता" के सिद्धांत

को लागू करते समय, वरिष्ठता को तभी महत्व दिया जाना चाहिए जब योग्यता [2023] 5 एस. सी.
आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और क्षमता लगभग बराबर है (बी. वी. शिवैया और ओआरएस देखें। (ऊपर); राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव और अन्य। बनाम संयुक्त क्षेत्रिया

ग्रामीण बैंक और अन्य।, (2010) 1 एससीसी 335)।

8.9 यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में और उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत योग्यता सूची के अनुसार, जिन उम्मीदवारों ने बहुत अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें पदोन्नति से वंचित कर दिया जाता है और उम्मीदवार /

सिविल जज (सीनियर डिवीजन), जिनके कम अंक/पट्टा मेधावी हैं, उन्हें पदोन्नत किया जाता है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता संख्या 1 ने 200 में से 135.50 अंक प्राप्त किए और याचिकाकर्ता संख्या 2 ने 200 में से 148.50 अंक प्राप्त किए, जिसके खिलाफ 101 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को पदोन्नति मिली है, जो "योग्यता-सह-वरिष्ठता" के सिद्धांत को प्रभावित कर रहा है।

9. इस प्रकार, हम इस बात से अधिक संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई विवादित चयन सूची और जिला न्यायाधीश के संवर्ग को पदोन्नति प्रदान करने वाली राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना अवैध और प्रासंगिक नियमों और विनियमों के विपरीत है और यहां तक कि अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के भी विपरीत है। (ऊपर)। इसलिए, हम प्रथम दृष्टया इस बात से अधिक संतुष्ट हैं कि ये स्थायी नहीं हैं। हालाँकि, हम अंत में रिट याचिका का निपटारा करने के लिए इच्छुक थे, हालाँकि, कुछ उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दुष्यंत दवे ने रिट याचिका का अंत में निपटारा नहीं करने का अनुरोध किया है और इसलिए, अंतरिम राहत के प्रश्न पर विचार कर सकते हैं, हम अंत में रिट याचिका का निपटारा नहीं कर रहे हैं। में लेना।

इस तथ्य पर विचार करें कि राज्य सरकार ने वर्तमान रिट के लंबित रहने के दौरान दिनांक 18.04.2023 की विवादित अधिसूचना जारी की है।

याचिका और वर्तमान कार्यवाहियों में इस न्यायालय द्वारा जारी सूचना की प्राप्ति के बाद और इस प्रकार, वर्तमान कार्यवाहियों की जानकारी होने के बावजूद, वर्तमान रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रहते हुए और जैसा कि इसमें ऊपर देखा गया है, राज्य सरकार इस न्यायालय द्वारा सुनवाई की अगली तारीख तक प्रतीक्षा कर सकती थी, जो 28.04.2023 पर थी और वर्तमान में संबंधित पदोन्नतियों ने पदोन्नति पद पर अपनी पोस्टिंग ग्रहण नहीं की है और इस तरह उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, हम गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा जारी 10.03.2023 और राज्य सरकार द्वारा जारी बाद की अधिसूचना दिनांक 18.04.2023 के आगे के कार्यान्वयन और संचालन पर रोक लगाते हैं। अर्थात्, संबंधित पदोन्नतियों को उनके मूल पदों पर भेजा जाना चाहिए जो वे अपनी पदोन्नति से पहले दिनांकित चयन सूची के माध्यम से रखते थे।

10.03.2023 और अधिसूचना दिनांक 18.04.2023।

हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि रविकुमार धनसुखलाल महिता और ए. एन. आर. वी. गुजरात और ओ. आर. एस. का उच्च न्यायालय। [एम. आर. शाह, जे.]

कि वर्तमान स्थगन आदेश उन पदोन्नतियों के संबंध में सीमित होगा जिनके नाम योग्यता के आधार पर योग्यता सूची में पहले 68 उम्मीदवारों में शामिल नहीं हैं, जिनकी प्रति प्रस्तुत की जाती है।

काउंटर के साथ उच्च न्यायालय द्वारा। अर्थात्, उन पदोन्नतियों की पदोन्नति, जिनके नाम योग्यता सूची में पहले 68 उम्मीदवारों में शामिल हैं, अन्यथा भी जारी रखी जाएगी और भले ही रिट याचिका की अनुमति दी जाए, उस मामले में भी उन्हें योग्यता के आधार पर पदोन्नति मिलेगी।

10. मामले के महत्व और अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को देखते हुए और

ओआरएस। (उपर्युक्त), जिसके अनुसरण में उच्च न्यायालय ने नियमों और विनियमों में संशोधन किया है, हमारी राय है कि मामले की सुनवाई भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा की जाए, हालांकि, प्रशासनिक पक्ष से भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश से उचित आदेश प्राप्त करने के अधीन और बाद में। रजिस्ट्री को 08.08.2023 पर अंतिम सुनवाई के लिए वर्तमान रिट याचिका को अधिसूचित करने का निर्देश दिया जाता है।

नि

देश जारी किए गए।

निधि जैन

(सहायक: राखी, एलसीआरए)